B-2

L-16

दिनांक
२५-11-23

Continue----

उदारवाद	उग्रवाद
आलोचना / कमियां	
- उदारवादियों ने अपने आन्दोलन को शहरी व शिक्षित वर्ग तक सीमित रखा और 1892 के अधिनियम के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नही कर सके।	उग्रवादियों द्वारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रयोग किये जाने से हमारे राष्ट्रीय संघर्ष का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रभावित हुआ जिसने बाद में साम्प्रदायिकता के विकास में भूमिका निभाई।
इनकी मांगों और कार्यक्रमों में लचीलापन / नम्यता देखते हुए तिलक जैसे नेताओं ने इनकी तुलना भिक्षुओं से की। कुछ विद्वानों ने उदारवादी रणनीति को 3P (Press, Petition, Prayer) कहकर आलोचना की।	स्वराज के अर्थ को लेकर भी उग्रवादी नेतृत्व निश्चित नही था। लाला लाजपत राय, तिलक व अरविन्द घोष अपने नजरिये से इसे परिभाषित कर रहे थे।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

सूरत फूट / विभाजन - उदारवाद व उग्रवाद के मध्य वैचारिक व सैद्धान्तिक मतभेद बढ़ते चले गये और कांग्रेस मध्यक्षपद को लेकर भी इनमें टकराहट बढ़ने लगी।

इसी बीच 1905 के बंग-भंग के विरुद्ध आन्दोलन की रणनीति को लेकर इनके मतभेद धरातल पर आ गये क्योंकि जहां उदारवादी आन्दोलन को बंगाल में सीमित रखना चाहते थे तो वहीं उग्रवादी इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना चाहते थे।

इन मतभेदों के चलते अन्तत: 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्टत: दो भागों में बंट गयी जिसका सर्वाधिक नुकसान हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को उठाना पड़ा और इसी का फायदा उठाते हुये अंग्रेजो ने 1909 में मार्ले मिन्टो एक्ट के द्वारा विशेष साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर भारत की सामाजिक - राजनैतिक एकता को खंडित करने का प्रयास किया।

प्रश्न: क्या कारण था कि 19वीं सदी का अन्त आते - आते नरम दल अपनी घोषित विचारधारा व राजनैतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र का विश्वास जमाने में असफल हो गये

उदारवादी नेतृत्व जिसने आरम्भिक कांग्रेस की बागडोर संभाली, वह भारतीयों के लिये महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करने में असफल रहा तो क्या राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवाद की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी ?

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- उदारवादी नेतृत्व की समीक्षा :-

- 1885 में स्थापित कांग्रेस का आरम्भिक नेतृत्व मुख्यत: अभिजात्य वर्गीय या उच्च मध्य वर्गीय रहा है उदाहरण स्वरूप 1885 के अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में से अधिकांश पत्रकार, वकील, जमींदार या व्यापारी वर्ग से थे।
- यह नेतृत्व पाश्चिमी शिक्षा से प्रभावित था और इनमे अंग्रेजी में बोलने की प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। इन्होंने अपने आन्दोलन को शहरी व शिक्षित वर्ग तक सीमित रखा क्योंकि

इनका मानना था कि जागरूक वर्ग ही आन्दोलन कर सकता है।

- इस नेतृत्व पर अभिजात्य वर्गीय होने का आरोप इसलिए भी लगाया जाता है कि सामान्यतः इन्होंने आम जनता के हितों की आवाज नहीं उठाई और यहाँ तक कि पंजाब भूमि राहत अधिनियम, जो कृषि सुधार से सम्बंधित था, का उदारवादियों ने समर्थन नहीं किया।

- उदारवादियों की रणनीति को लेकर भी इन्हें भिक्षु तक कहा गया तथा इनके सम्मेलनों को उत्सवीय तमाशा कहकर आलोचना की गयी कि ये वास्तव में भारतीयों के लिए कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते ही नहीं थे।

इन सभी आरोपों को नकारा तो नहीं जा सकता किन्तु उदारवादी नेतृत्व के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष में इनकी महत्ता को स्वीकारना होगा -

↳ राष्ट्रीय स्तर पर संगठित राष्ट्रवाद की नींव उदारवादियों द्वारा ही रखी गयी इसीलिए ये अपने दौर के छात्र व शिक्षक दोनों ही थे।

↳ उदारवादियों का सबसे बड़ा दायित्व यह था कि वे दीर्घकालिक राष्ट्रीय संघर्ष का ऐसा प्रारूप तैयार करें जिसे सभी की स्वीकार्यता हो, इसीलिए धर्म निरपेक्षता को अपनाते हुए इन्होंने बड़ी शिद्दत से ऐसे राजनैतिक प्रशासनिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किये जो आजादी तक आन्दोलन का हिस्सा बने रहे।

KGS IAS

- उदारवादी नेतृत्व पर केवल अभिजात्य वर्गीय हितों के प्रतिनिधि होने का आरोप भी पूरी तरह स्वीकारा नहीं जा सकता क्योंकि इनकी मांगों में - लगान में कमी व श्रम सुधार जैसे विषय भी शामिल थे।

निष्कर्षतः उदारवाद की राजनैतिक मांगे, कार्यक्रम व उपलब्धियों को लेकर आलोचना तो की जा सकती है किन्तु यह तो स्वीकारना ही होगा कि उदारवाद ने ही राष्ट्रीय आंदोलन की ऐसी सुदृढ नींव तैयार की जिस पर आगे बढ़ते हुए उग्रवादी नेतृत्व व गांधी ने भारत को आजादी के दरवाजे तक पहुँचा दिया और उदारवादियों की औपनिवेशिक शासन की आर्थिक मिमांशा को किसी दृष्टि से कम नहीं माना जा सकता।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

बंग-भंग / बंगाल विभाजन :-

- जुलाई 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा और अक्टूबर में इस विभाजन को लागू कर दिया गया।

सरकारी उद्घोषणा के अनुसार बंगाल का क्षेत्रफल अत्यधिक विस्तृत होने के कारण, वहां प्रशासनिक असुविधा हो रही है अतः बेहतर प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल का विभाजन किया जाना उचित है (जैसा कि 1874 में असम को अलग प्रांत बनाया जा चुका था) अतः यह कोई अनूठा निर्णय नहीं था।

कर्जन की यह उद्घोषणा दिखावा मात्र था, वस्तुतः यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का श्रेष्ठ उदाहरण था। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन बंगाल

भारतीय राष्ट्रवाद का पावर हाउस था और धीरे-धीरे वहां राष्ट्रवादी भावना जुझारू रूप धारण करने लगी थी अतः अंग्रेजों को अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रवाद को कमजोर करना आवश्यक लगा और दो आधारों पर यह विभाजन किया गया-

1. पश्चिम बंगाल में भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास।
2. पूर्वी बंगाल में धार्मिक आधार पर राष्ट्रवाद को कमजोर करने का प्रयास।

बंगाल विभाजन की चर्चा शुरू होने के साथ ही बंगाल की एकता को कायम रखने के लिए वहां विरोध प्रदर्शन आरम्भ हो गये। किन्तु इसके बावजूद जब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजित कर दिया गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज वहां के लोगों की भावनाओं को कोई महत्व नहीं देते अतः इसके विरोध में लगभग सम्पूर्ण बंगाल में हड़ताल व प्रदर्शन होने लगे और विशेषतः इस निर्णय ने युवाओं को आक्रोशित कर दिया कि उदारवादी रणनीति से अब कुछ अलग विकल्प तलाशने होंगे।

बंगाल विभाजन के निर्णय से असन्तुष्ट होकर भारतीय राष्ट्रवाद में कुछ नयी जुझारू प्रवृत्तियों का उदय हुआ और इसीलिए अब उग्रवाद व क्रांतिकारी गतिविधियां लोकप्रिय होने लगीं तथा अब अपने अधिकारों को पुरस्कार स्वरूप मांगने के लिए नहीं बल्कि स्वावलम्बन के आधार पर सत्ता से इसे छीनने को महत्वपूर्ण माना जाने लगा।

KGS IAS

इस प्रकार बंग-भंग के विरोध में राष्ट्रीय भावना कमजोर होने की जगह और प्रखर होने लगी तथा बंगाल से बाहर प्रसारित होकर राष्ट्रीय स्वरूप धारण करने लगी और बंग-भंग के विरोध में उत्पन्न स्वदेशी आन्दोलन आधुनिक भारत के इतिहास का पहला जन-आन्दोलन माना गया। यह इतना लोकप्रीय साबित हुआ कि अन्ततः 1911 में बंग-भंग का निर्णय वापस लेना पड़ा और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित कर दी गयी।

प्रश्न- 1905 के बाद भारत में नयी राष्ट्रीय जुझारू प्रवृत्तियों का उदय हुआ चर्चा करें।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

स्वदेशी आन्दोलन

स्वदेशी एक विचारधारा के रूप में 19वीं सदी के अन्त तक प्रचलित हो चुकी थी किन्तु इसने आन्दोलन का रूप तब धारण किया जब बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा था यह वास्तविक अर्थों में स्वदेशी आन्दोलन था क्योंकि मानव जीवन के प्रायः सभी पक्षों को स्वदेशी मूल्यों से जोड़ने की कोशिश की गयी और मुख्यतः 4 कार्यक्रमों को आधार माना गया— राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी तथा निष्क्रीय प्रतिरोध।

शिक्षा के क्षेत्र में -

नेशनल स्कूल ऑफ बेंगोल तथा शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी तथा सतीश चन्द्र मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा का मसौदा प्रस्तुत किया गया।

आर्थिक क्षेत्र में -

स्वदेशी आन्दोलन में - स्वदेशी व बहिष्कार को पूरक के रूप में देखा गया अर्थात जिन ब्रिटिश वस्तुओं का विहिष्कार किया गया उनके स्वदेशी उत्पादन का प्रयास किया गया। स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की आर्थिक निर्भरता को ब्रिटेन पर कम किया जाये और इसी सन्दर्भ में मद्रास में स्वदेशी स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, कलकत्ता में नेशनल केमिकल फैक्ट्री तो जमशेदपुर में टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गयी।

कला व आध्यात्म के क्षेत्र में -

- भारतीय कला संस्कृति व आध्यात्म को पाश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराये बगैर स्वदेशी आन्दोलन का कोई महत्व नही रह जाता। कहा जाता है कि राजनैतिक गुलामी अस्थायी होती है किन्तु मानसिक / सांस्कृतिक गुलामी दीर्घ-कालिक होती है।

स्वदेशी आन्दोलन के दौरान चित्रकला को पाश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराने के लिए इण्डो-ओरिएन्टल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गयी, जिसकी पहली प्रदर्शनी

नन्द लाल बोस को मिली और अविन्द्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में चित्रकला में पुनर्स्थापनावाद को बढ़ावा दिया गया।

इसके साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र को भौतिकतावाद से मुक्त कराने का प्रयास किया गया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR